MR. SPEAKER: Q. No. 455.

SHRI VASANT SATHE: Sir, I would like to know if perishable goods are to be destroyed, what is the value of these perishable goods? (*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I rise on a point of order. He must assure the House.... (*Interruptions*) Let the Minister give an assurance on this question.

SHRI H. M. PATEL: Nothing has been destroyed so far. As far as perishable goods are concerned, I can only say this that whatever decision we take, we will inform the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I rise on a point of order.

SHRI MANI RAM BAGRI: प्वाइंट आफ आर्डर । जो सवाल किए गए.....

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is your point of order? Don't make a speech on raising a point or order.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am raising a point of order.

Sir Rs. 43 crores of goods are destroyed every year.

माननीय श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने यह कहा कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वे या तो एक्सपोर्ट किए जाएंगे या डिस्ट्राय किए जाएंगे । डिस्ट्राय का शब्द उन्होंने दबी आवाज़ में कहा जो हमें तो सुनाई दे गया और माननीय मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने यह कहा कि जो डेसीशन होगा वह सदन के सामने बताया जायगा । सदन यह चाहता है कि किन्हीं हालात में भी हर साल 43 करोड़ रुपये का माल री-एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, वह डिस्ट्राय ही होगा . . . (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is your point of order?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Minister is not giving proper information to the House.

MR. SPEAKER: This is no point of order.

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो सवाल माननीय सदस्य करें, जो सावल सदन से रखे जायें उनका जवाब मन्त्री महोदय दें । आप गार्जियन हैं सवाल के जवाब के और वह जवाब वेग नहीं होना चाहिये, गोल माल नहीं होना चाहिए बल्कि स्पष्ट और साफ होना चाहिए । आप मंत्रियों को हिदायत करें कि वे तैयारी करके आयें । यहां पर मंत्री जी कुछ कहते हैं और राज्य मंत्री जी कुछ कहते हैं, गोलमाल जवाब देते हैं । जब सदन बैठा है, लोकसभा चल रही है और एक चीज़ यहां पर आ गई तो मंत्री जी डेस्ट्राय करने का डिसीज़न लेने वाले कौन होते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : डेस्ट्राय करने के बारे में डिसीज़न मैंने नहीं लिया है ।

Developments of sites of tourist interest in Madhya Pradesh during Fifth Five Year Plan period

*456. SHRI SUKHENDRA SINGH:
SHRI SHARAD YADAV:

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some suggestions were made by the State of Madhya Pradesh for development of sites of tourist interest during the Fifth Five Year Plan period; and

(b) if so, the details thereof and the progress regarding the completion as well as the expenditure involved therein?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). अप्रैल / मई 1977 में राज्य सरकार से सुझाव प्राप्त हुए थे जिनमें खजुराहो, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, कान्हा, मांडू, सांची, उज्जैन, महेश्वर, ओमकारेश्वर,

भोपाल तथा इन्दौर में पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल था। छठी योजना पर विचार विमर्श करते समय इनकी जांच की जाएगी।

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो नाम बताए गए हैं उनमें चित्रकूट, रामबन, ओरछा—यह नाम भी शामिल हुए हैं क्या ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक मैं आशय समझा, माननीय सदस्य का सवाल यह था कि मध्य प्रदेश शासन की जो प्रस्तावित योनजा है उसकी जानकारी दी जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रस्तावित योजना है, जो उन्होंने केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास भेजी है उसकी जानकारी मैंने दी है। उसमें विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य शायद चाहते हैं मैं फिर से पढ़ दूं। मध्य प्रदेश शासन से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसमें खुजराहो, पंचमढ़ी, भेडाघाट, कान्हा, मांडू, सांची, उज्जैन, महेश्वर, ओमकारेश्वर, भोपाल तथा इन्दौर में पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल था।

श्री सुखेन्द्र सिंह : मैं जो नाम बता रहा हूं उनके बारे में क्या सरकार विचार नहीं करना चाहती ? यह तो बड़े महत्व के स्थान हैं। चित्रकूट, रामबन, ओरछा—यह जो नाम मैंने गिनाए हैं वहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। मंत्री महोदय जब गए थे तो वहां भी गए थे। इसलिए इनको भी लिया जाए। यह स्थान वैसे भी प्राकृतिक केन्द्र हैं, और वहां नदी है पानी बहता है इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में बाहर से भी पर्यटक आते हैं, प्रदेश के तो आते ही हैं इसलिए वहां पर पर्यटक केन्द्र बनाए जायं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं वहां गया जरूर था लेकिन जब तक राज्य शासन से इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी कि वहां कितने पर्यटक आते हैं, उसमें देश के कितने हैं और विदेशी कितने हैं और वहां किस तरह से खर्चा करना चाहिए—इसकी योजना जब तक राज्य सरकार अपनी ओर से शुरू नहीं करती तब तक हमारे लिए किसी स्थान को तत्काल अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का समझ कर काम शुरू कर देना, यह सम्भव नहीं है। जब मैं वहां पर गया था तो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी हमारे साथ थे और मैंने उनसे कहा है कि समूचे आंकड़े दें तो छठी पंचवर्षीय योजना में हम उस पर विचार करेंगे।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, केवल मध्य प्रदेश में ही इतने अधिक प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र हैं कि मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश इतना सम्पन्न नहीं होगा लेकिन पिछले तीस वर्षों के चलते वहां पर जो राशि विगत दिनों खर्च की गई वह बहुत कम थी। तो कोई ऐसी व्यवस्था होगी क्या जिसके अन्तर्गत जो भी ऐसे स्थान हैं, जो भी ऐसे केन्द्र हैं जो बहुत सुन्दर हैं और जिनकी विश्व में कोई मिसाल नहीं है उनका विकास किया जा सके। मैं भेड़ाघाट की मिसाल देता हूं, उसको आप देखें तो दंग रह जायेंगे कि दुनिया में इस तरह का भी कोई प्राकृतिक केन्द्र है लेकिन आज तक उस पर कोई खर्च करने की व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा यह कहना है कि ढिलाई बन्द करके प्रदेश सरकार की अड़चन का जो मामला,

है उस को समाप्त कर के, हमारे यहां जो देखने काबिल स्थल हैं, उन को ठीक करें। खुजराहों में जो स्थानीय लोग जाते हैं, उनको बहुत खर्चा पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां जो पर्यटक केन्द्र हैं उनके विकास के लिए जी-जान से कोशिश करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : पिछले 30 साल में क्या हुआ, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, सभी राज्यों में उन के प्राकृतिक आकर्षण के केन्द्रों के समुचित विकास और हमारे जितने सीमित साधन हैं, सबके साथ समान व्यवहार हो, इस दृष्टि से सबसे पहला यह काम किया है कि राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में सब राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने राज्यों के ऐसे स्थानों का पर्सपेक्टिव प्लान हम को बना कर भेजें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लगभग आधे राज्यों से पर्सपेक्टिव प्लान्ज हम को मिले हैं, बाकी राज्यों से नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश का पर्सपेक्टिव प्लान हम को मिल गया है।

मैं भेड़ाघाट गया था। वहां का महत्व मैं अच्छी तरह से महसूस करता हूं निश्चित रूप से वह एक विकसित पर्यटन केन्द्र होना चाहिए। छठी योजना में इसके लिए क्या कुछ किया जा सकेगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : जबलपुर के नजदीक दो स्थल हैं : भेड़ाघाट और कान्हाकिसली--ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भेड़ाघाट का उल्लेख भाई शरद यादव ने अभी किया है वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है वहां पर प्रकाश की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, मोटल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कान्हा-किसली जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। क्या मंत्री जी बतलायगे कि इन दो स्थानों--भेड़ाघाट और कान्हा-किसली के विकास के लिए पांचवे प्लान में कितना खर्च करने की योजना है और कान्हा-किसली तक हवाई जहाज ले जाने की व्यवस्था हो सकेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : छठी योजना में कितना खर्च करेंगे, मैं इस समय नहीं कह सकता हूं। जहां तक भेड़ाघाट का सम्बन्ध है इस पर विचार हो रहा है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्लानिंग कमीशन से कितनी राशि हमको उपलब्ध होती है।

मैं आपकी जानकारी में यह बात भी ला दूं कि इन स्थानों पर सड़क बनाने का काम, पानी की व्यवस्था का काम राज्य सरकार का है ....

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मैंने पानी और सड़क के लिए नहीं कहा है--होटल, मोटल, बिजली, लिफ्ट और हवाई जहाज के लिए कहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक बिजली का सवाल है--माननीय सदस्य राज्य सरकार से आग्रह कर के बिजली लगवाने का काम करें। हमारा जो काम है, उसमें हम ....

श्री मनीराम बागड़ी : इसका क्या मतलब है। हम लोक सभा के मंत्रियों से बात करें या उन से बात करें--इस को आप देखिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं--सड़क, बिजली और

पानी की—इस में भी हम ने राज्य सरकारों को अनुदान दिया है, लेकिन उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

जहां तक भेड़ाघाट में आवास की व्यवस्था का प्रश्न है—राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से वहां पर एक फारेस्ट लाज बनाया गया है जो चालू होने वाला है। बोटिंग का काम वहां की जो जनपद पंचायत है, उस की तरफ से शुरू किया जा रहा है। कुल मिला कर मैं समझता हूं पर्यटकों की आवक को देखते हुए जो विकास कार्यक्रम होगा उस पर विचार किया जाएगा।

कान्हा के सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूं—कान्हा में हम स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक फारेस्ट लाज बनवाने जा रहे हैं; वहां पर एक टूरिस्ट-कोच की व्यवस्था भी हमने की है। पानी के लिए हमने स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को पैसा दिया है। वहां इस समय जितनी आवश्यकता है, उसे देखते हुए हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े।

जहां तक कान्हा को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रश्न है, फिलहाल यह सम्भव नहीं है। जबलपुर हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है और जबलपुर से कान्हा बहुत दूर नहीं है। अगर सड़क यातायात की व्यवस्था हो जाएगी, तो पर्यटक सुगमता से कान्हा जा सकेंगे। इस लिए कान्हा को हवाई मार्ग से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।

MR. SPEAKER: Shri Lakkappa.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जो नाम गिनाए हैं, जिनके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके पास प्रस्ताव भेजा है, ये स्थल ऐसे हैं, जिनका पहले से कुछ विकास हो चुका है और जहां कुछ न कुछ सुविधायें पर्यटकों के लिए हैं, ...

MR. SPEAKER: You are not raising a point of order. Please do not make a speech. There is no point of order. Don't record.

SHRI Y. P. SHASTRI: * *

MR. SPEAKER: Order, order. Nobody can rise on a point of order and then put a supplementary. He rose on a point of order.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have not called him for supplementaries. It does not mean that every day he should get a chance.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Unless I permit him, he cannot put the question. Do we have a separate rule for one Member?

SHRI Y. P. SHASTRI: I seek your protection, Sir, I have put a supplementary.

MR. SPEAKER: You rose on a point of order.

SHRI Y. P. SHASTRI: No, no. I seek your protection.

MR. SPEAKER: Let us look at the records. This type of things cannot be allowed. Every day I find the hon. Member rising on a point of order, and then putting a supplementary.

**Not recorded.

SHRI K. LAKKAPPA: India is a tourist paradise. While replying, the Minister stated that proposals sent by the States will be considered. I would like to ask him: what are the criteria and guidelines adopted for improving the tourist spots in the country? Will the Minister consider proposals given by the States; or will his Ministry itself prepare proposals for improving and developing the tourist centres? Basic facilities and amenities are not provided to the domestic as well as international tourists, to attract them to the centres. How many proposals already sent by the respective States are pending in his Ministry; and what are the amounts that are going to be spent to improve such tourist centres in this country?

MR. SPEAKER: The question relates to Madhya Pradesh.

SHRI K. LAKKAPPA: I have put my question on the points arising out of the answer given to a supplementary.

SHRI A. BALA PAJANOR: While replying to the hon. Member Mr. Sharad Yadav, the Minister said that he was giving serious attention to the proposals coming from the State government. (*Interruptions*) Window dressing is being made every time by the Ministry of Tourism. The Minister also said that the earlier Government was not doing much work. My Chief Minister has given a proposal for an airport at Pondicherry. Is the hon. Minister considering that proposal at all?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं दोनों माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब में इतना कहना चाहता हूं कि यह सही है कि राज्य सरकारों से हमने प्रस्ताव मंगवाये हैं और उन पर विचार करेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारों से जो प्रस्ताव मिलें उन्हीं तक हम अपने को सीमित रखें। जो भी स्थान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन जहां तक फाइनेंशियल अलोकेशंस का सम्बन्ध है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्लानिंग कमीशन कितनी मंजूरी देता है।

पांडिचेरी के प्रपोजल की मेरे पास जानकारी नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान के केवल 16 राज्यों से हमें जानकारी मिली है।

From 16 States we have recived prespective plans.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Credit project negotiated by A.R.D.C. with I.D.A.

*447. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the second Agricultural Refinance and Development Corporation Credit Project was negotiated in April, 1977 by the Government and the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) with the International Development Association (IDA) an affiliate of the World Bank, for a credit of $ 200 million;

(b) the rate of interest and/or service charge per cent per annum charged by the I.D.A. to the Government;

(c) the rate of interest per cent per annum to be charged by the Government to the ARDC;

(d) the rate of interest per cent per annum to be charged by the ARDC on refinance for various development schemes; and

(e) the rate of interest per cent per annum to be charged by the land development banks, for various development schemes to the ultimate borrower?